

मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में चल लक्ष्य

	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	(मौजूदा बाजार मूल्य पर)	
			के लिए लक्ष्य	
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1. प्रभावी राजस्व घाटा	2.2	1.8	0.0	0.0
2. राजस्व घाटा	3.3	3.0	2.0	1.5
3. राजकोषीय घाटा	4.6	4.1	3.6	3.0
4. सकल कर राजस्व	10.2	10.7	11.2	11.5
5. वर्ष के अंत में कुल बकाया देनदारियाँ ²	46.0	44.8	43.1	41.0

टिप्पणी:—

1. "स.घ.उ." से आशय 2004-05 से नई श्रृंखला के अनुसार मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद है।
2. "कुल बकाया देनदारियों" में वर्तमान विनिमय दरों पर विदेशी सरकारी ऋण शामिल है। अनुमान के लिए अचल विनिमय दरें परिकल्पित हैं। देनदारियों में एनएसएसएफ तथा एमएसएस देनदारियाँ, जो कि केंद्रीय सरकारी घाटे के वित्तपोषण के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती हैं, शामिल हैं।
1. मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान चुनिंदा राजकोषीय संकेतकों संबंधी निष्पादन और आगामी वित्तीय वर्षों के लिए वर्तमान लक्ष्य ऊपर दिए गए हैं। प्राप्ति, विशेषकर कर राजस्व में दबाव के बावजूद राजकोषीय घाटे बजट 2013-14 में अनुमानित 4.8 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 4.6 प्रतिशत पर आ गया है। 22 मई 2013 को यूएस फेडरल द्वारा प्रमात्रात्मक सहजता में कमी आने के संकेत मिलने और उच्च मुद्रस्फीति की प्रवृत्ति से व्यापार एवं राजकोषीय मंच दोनों पर घाटे का खतरा होने से विनिमय दर में दबाव आया। तथापि, सकारात्मक सक्रिय नीतियों को अपनाकर सरकार ने सफलतापूर्वक दोनों घाटों से निजात पायी है। मौजूदा वित्त वर्ष में सामना की जाने की चुनौतियों को देखते हुए उपर्युक्त सारणी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पैटर्न को दर्शाती है।
2. यह स्मरणीय होगा कि केलकर समिति की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए सरकार ने विगत वित्त वर्ष में मध्यवार्षिक नीति का कार्यान्वयन किया तथा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का मार्ग अपनाया। वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजकोषीय निष्पादन जैसाकि अनंतिम लेखाओं में दर्शाया गया है, आशा से कहीं बेहतर था। यह उल्लेखनीय है कि राजकोषीय नीति में परिवर्तन को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है। विगत वित्तीय वर्ष के द्वितीयार्ध में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के उपायों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करके मौजूदा वर्ष का बजट व्यय और प्राप्ति का वास्तविक आंकलन करके प्रस्तुत किया गया था। वास्तविक आंकड़े की तुलना में 11.4 प्रतिशत आयोजना-भिन्न व्यय में सब्सिडी हेतु पर्याप्त आवंटन शामिल किया गया। इसी प्रकार आयोजना पक्ष में विगत वर्ष में वास्तविक आंकड़े की तुलना में 34 प्रतिशत विकास की बजट व्यवस्था की गई थी। तथापि, व्यय में वृद्धि को कर और अन्य प्राप्ति दोनों के संबंध में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपायों द्वारा संतुलित किया गया।
3. तथापि, वैश्विक और देशीय दोनों कारकों की वजह से अर्थव्यवस्था में सामना की गई चुनौतियों ने वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही बजट लक्ष्यों को दबाव में रखा। पहला 22 मई, 2013 को यूएस फेड द्वारा प्रमात्रात्मक सहजता में कमी आने के संकेत मिलने के बाद विनिमय दर पर दबाव बढ़ा। इसके बाद डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में दो से तीन माह तेजी से मूल्यहास देखी गई। यद्यपि इसी प्रकार की समस्याओं का सामना अन्य उभरते देश भी कर रहे थे; भारत में बढ़ते व्यापार घाटा से अतिरिक्त दबाव आया।
4. भारतीय रिजर्व बैंक को अल्पावधिक ब्याज दर बढ़ाते हुए वित्तीय बाजारों में हस्तक्षेप करना पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप उधार की लागत बढ़ी। तथापि, सरकार निवेश जुटाने और सोने का आयात भी कम करने के लिए नीतिगत सुधार के कार्य में सकारात्मक रूप से सक्रिय बनी रही। अनुक्रम में सरकार और केन्द्रीय बैंक द्वारा किए गए कारगर कार्यों के परिणाम आए और कलेंडर वर्ष 2013 के अंत तक भुगतान संतुलन की स्थिति काफी सहज हो गई। चालू खाता घाटा की स्थिति नीतिगत उपायों की वजह से सुधर गई और पहली तिमाही में 21.8 बिलियन अमरीकी डालर की

तुलना में दूसरी तिमाही में यह घाटा 5.2 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गया। यह आशा की जाती है कि वित्त वर्ष 2013-14 में चालू खाता घाटा लगभग 45 बिलियन अमरीकी डालर होगा, जो विगत वर्ष की तुलना में काफी कम है।

5. असमर्थनकारी बाह्य वातावरण, घरेलू संरचना संबंधी अड़चनों और मुद्रास्फीतिकारी दबाव के रूप में अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद विकास की गिरती प्रवृत्ति में उलटफेर करके इसमें वृद्धि की जानी थी। सरकार अपने नीतिगत सुधारों और राजकोषीय सुदृढीकरण के मुद्दों पर दृढ़ बनी रही। प्राप्तियों पर दबाव के बावजूद आयोजना व्यय को प्राथमिकता देने हेतु सचेत निर्णय लिये गये। इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में बाद के महीने हेतु समानुपातिक राजकोषीय घाटा बढ़ गया। तथापि, सरकार ने राजकोषीय सुदृढीकरण की अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की। लक्षित संसाधनों को हासिल करने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए, जबकि बजटीय व्यवस्था में निर्धारित घाटे के स्तर पर बने रहने की दृष्टि से व्यय का योक्तिकीकरण किया गया।

6. राजकोषीय घाटा संबंधी निष्पादन इस तथ्य को देखते हुए अधिक विश्वसनीय है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार केन्द्र की कुल निवल राजस्व प्राप्तियों में ₹27,078 करोड़ की राजस्व कमी रही। बजटीय स्तर से आयोजना-भिन्न व्यय में ₹4,927 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई यद्यपि मुख्यतः अधिक ईंधन सब्सिडी के कारण ₹24,432 करोड़ तक सब्सिडी में अधिक वृद्धि हुई थी। उल्लेखनीय है कि मितव्ययिता के अधीन आयोजना-भिन्न व्यय में बचत द्वारा इस वृद्धि के हिस्से को प्रतिस्तुलित कर दिया गया। अतः राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2013-14 में 3.3 प्रतिशत के बजटीय स्तर पर बना रहा। बेहतर राजकोषीय प्रबंधन और व्यय पर नियंत्रण के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा स.घ.उ. के 4.6 प्रतिशत पर आ गया, इसमें 4.8 प्रतिशत के बजट अनुमान से 0.2 प्रतिशत का सुधार आया।

7. राजकोषीय प्रबंधन का विश्लेषण सरकार के घटते संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना है। घटते निर्यात और कम औद्योगिक विकास के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ओर करों में बजटीय स्तर से विचलन दर्शित हो रहा था। केन्द्र को करों पर ₹48,052 करोड़ निवल रूप से कम प्राप्त होने का कारण अर्थव्यवस्था में समग्र गिरावट का परिणाम था। विशेषकर अप्रत्यक्ष कर और इससे अधिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कमी की प्रवृत्ति देखी गई। वास्तव में, वित्तीय वर्ष के अधिकांश भाग में विगत वर्ष की इसी अवधि में किए गए सग्रहण के मुकाबले उत्पाद शुल्क संग्रहण में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, कर-भिन्न राजस्व में ₹20,974 करोड़ की वृद्धि हुई इसके बाद प्रतीकात्मक नीलामी और उच्च लाभांश के प्रति अच्छी अनुक्रिया प्राप्त हुई। ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों के लक्ष्य में संशोधन करके ₹29,824 करोड़ कर दिया गया। यह बजट अनुमान 2013-14 में ₹66,468 करोड़ था और संशोधित अनुमान में ₹36,644 करोड़ रूपए रखा गया। यह कमी, मुख्य रूप से,

वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता के चलते विनिवेश से प्रत्याशा से कम प्राप्तियों के कारण रही।

8. इसके साथ ही साथ सरकारी व्यय को नियंत्रित करने और निजी निवेश के लिए अधिक संभावना बनाने तथा मौद्रिक नीति को उदार बनाने के उभरते दृष्टिकोण की तर्ज पर सरकार ने व्यय सीमित करने का कार्य किया। सरकार का कुल व्यय ब.अ. 2013-14 में ₹1665297 करोड़ रखा गया था जो कम कर के सं. अ. 2013-14 में ₹1590435 करोड़ कर दिया गया। तथापि मुख्य सब्सिडियों पर व्यय ब.अ. 2013-14 में रखे गए ₹220972 करोड़ से बढ़कर सं.अ. 2013-14 में ₹245452 करोड़ कर दिया गया। समग्र आयोजना-भिन्न व्यय ब.अ. में ₹11,09,975 करोड़ से बढ़कर ₹11,14,902 करोड़ हो गया, जो मामूली वृद्धि दर्शाता है। प्रमात्रात्मक सहजता में कमी की घोषणा के बाद रूपए के मूल्य में गिरावट पर नियंत्रण रखने के लिए वित्तीय बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के कारण ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि हुई। दरों के बढ़ने में मुद्रास्फीति दबाव का भी हाथ था, जिसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा ब्याज भुगतान में संशोधन किया गया और इसे ₹3,70,684 करोड़ के आरंभिक अनुमान से बढ़ाकर ₹3,80,066 करोड़ किया गया।

9. वित्तपोषण पक्ष में दिनांकित प्रतिभूतियों से बाजार उधार को जनवरी 2014 के तीसरे हफ्ते के उधार कलेंडर से नीलामी रद्द करके ₹15,098 करोड़ कम किया गया। राजकोषीय स्थिति का प्रबंधन करने हेतु सरकार की मंशा बताने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम था और इसे बाजार द्वारा सकारात्मक देखा गया। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन से सरकार ने घाटा अनुमानों में बेहतर प्रदर्शन किया, इसके द्वारा बाजार में इस कटौती को घटते विदेशी उधार में कटौती करने के लिए बेहतर संभावना बढ़ी। बाजार में इस कटौती को घटते विदेशी उधार की पृष्ठभूमि में देखा जाना है। निवल विदेशी उधार ब.अ. 2013-14 में रखे गए ₹10,560 करोड़ की तुलना में सं.अ. 2013-14 में ₹5,440 करोड़ किया गया। अल्पावधिक राजकोषीय हुण्डियों से उधार ब.अ. में ₹19844 करोड़ से बढ़ाकर सं.अ. 2013-14 में ₹22,678 करोड़ किया गया।

2014-15 के लिए राजकोषीय परिदृश्य

10. सरकार ने वित्त वर्ष 2012-13 में मध्यावधिक नीतिगत समीक्षा से शुरू किए गए राजकोषीय नीति के क्रियान्वयन को वित्तीय वर्ष 2013-14 में जारी रखा। राजकोषीय नीति 2014-15 की अभिकल्पना अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में भारत द्वारा सामना की जाने वाली वृहद् आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए की गई है। आर्थिक विकास, जो वित्त वर्ष 2011-12 से गिरना आरंभ किया, ने वित्त वर्ष 2013-14 में 4.5 प्रतिशत से बढ़ते हुए उलटफेर किया। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2013-14 में यह बढ़कर 4.9 प्रतिशत हो जाएगा। तथापि, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति प्रमुख देशों में विकास के स्थिर रहने तथा यूएस फेड के प्रमात्रात्मक सहजता में कमी करना आरंभ करने से अनिश्चित बना रही। सरकार अपने दोहरे घाटे को नियंत्रित करने के लिए अपनी वचनबद्धता में अडिग बनी रही।

11. राजकोषीय सुदृढीकरण प्रक्रिया पर अपना ध्यान वापस लाकर सरकार ने सं.अ. 2013-14 में राजकोषीय घाटा स.घ.उ. के 4.6 प्रतिशत से कम करके ब.अ. 2014-15 में स.घ.उ. के 4.1 प्रतिशत पर लाने हेतु उपाय किए हैं। राजकोषीय घाटे में 0.5 प्रतिशत बिंदु तक की यह कमी मुख्यतया राजस्व प्रेरित थी। कुल व्यय सं.अ. 2013-14 में रखे गए 14.0 प्रतिशत से स.घ.उ. का 0.3 प्रतिशत कम करके ब.अ. 2014-15 में 13.7 प्रतिशत किया गया है। कर राजस्व में स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह स.अ. 2013-14 में रखे गए 10.2 प्रतिशत से बढ़कर ब.अ. 2014-15 में 10.7 प्रतिशत की गयी। तथापि, कर-भिन्न राजस्व सं.अ. 2013-14 में स.घ.उ. का 1.7 प्रतिशत था जो 0.3 प्रतिशत कम करके ब.अ. 2014-15 में 1.4 प्रतिशत अनुमानित है। राजस्व घाटे का अनुमान ब.अ. 2014-15 में स.घ.उ. का 3.0 प्रतिशत है। यह वित्त वर्ष 2013-14 में 3.3 प्रतिशत था। राजस्व घाटा ब.अ. 2014-15 में स.घ.उ. का 3.0 प्रतिशत अनुमानित है। राजस्व घाटे का ब.अ. स.घ.उ. का 3.3 प्रतिशत था जिसे 2013-14 में सं.अ. में बनाए रखा गया है। यह तथ्य कि राजस्व घाटा को स.अ. पर बनाए रखा गया है और ब.अ. में इसके घटने का अनुमान लगाया गया है, राजकोषीय सुदृढीकरण की कार्ययोजना के अनुरूप राजकोषीय व्यय में सुधार लाने की सरकार की प्रेरणा का द्योतक है। बढ़ते सब्सिडी बिल का समाधान करने के लिए अनेक नीतिगत उपाय किए गए, विशेषकर बाजार मूल्यों से सम्बद्ध करने के लिए प्रगामी रूप से डीजल की कीमत बढ़ाने के निर्णय के प्रगामी परिणाम आएंगे। यह आशा की जाती है कि बेहतर व्यय प्रबंधन से वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में राजस्व घाटा क्रमशः 2.0 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत कम होगा।

12. चूंकि राजस्व व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के रूप में दिया जाता है, सरकार के प्रभावी राजस्व घाटे पर दृष्टिपात करना प्रासंगिक होगा। प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व खाते में उपर्युक्त अनुदान संघटकों में गुणक के पश्चात ब.अ. 2014-15 में स.घ.उ. का 1.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसे अनुमान अवधि में समाप्त करने का प्रस्ताव है। राजस्व खाते में असंतुलन के इसी घटक का व्यय प्रबंधन और राजस्व बढ़ाकर सबसे पहले समाधान करने की आवश्यकता है। तथापि, यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि संशोधित एफआरबीएम अधिनियम, 2012 और उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अधीन सरकार ने स.घ.उ. के 2 प्रतिशत तक राजस्व घाटा कम करने और 31 मार्च 2015 तक प्रभावी राजस्व घाटा समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। अंतरिम बजट 2014-15 में प्रस्तुत बजट अनुमानों के अनुसार, निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मिश्रित व्यय की संरचना में सुधार लाने की आवश्यकता है। इससे अधिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मोड में आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा ताकि प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा या कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से अधिक महत्वपूर्ण सूचना हासिल की जा सके।

13 स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में, सरकार की कुल देनदारियों में हालिया रुझान से कमी जारी रहेगी। 2013-14 के अंत में,

सरकार की कुल देनदारी स.घ.उ. की 46.0 प्रतिशत आंकी गई है, जो 2014-15 की समाप्ति तक घटकर 44.8 प्रतिशत हो सकती है। लगातार रुझान में कमी के चलते यह कम होकर 2015-16 में 43.1 प्रतिशत तथा 2016-17 में 41.0 प्रतिशत पर आ सकती है। सरकार के ऋण - स.घ.उ. के अनुपात में उत्तरोत्तर कमी ब्याज के बोझ को कम करेगी तथा अतिरिक्त उधार का सहारा लिए बगैर विशेषकर अवसंरचना विकास पर खर्च करने के लिए सरकार के पास अधिक गुंजाइश होगी।

14. सकल कर राजस्व के संशोधित अनुमान 2013-14 में स.घ.उ. के 10.2 प्रतिशत से बढ़कर बजट अनुमान 2014-15 में 10.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, (जो सं.अ. 2013-14 से 19.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है)। तथापि, यह 2007-08 के दौरान प्राप्त स.घ.उ. के 11.9 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से अभी कम है। अर्थव्यवस्था के पुनः विकास पथ पर आने से स.घ.उ. अनुपात के स्तर को वापस प्राप्त करना संभव होगा। मध्यकालिक लक्ष्यों में, स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल कर संग्रहण 2015-16 में 11.2 प्रतिशत तथा 2016-17 में 11.5 प्रतिशत प्राप्त किया जाना संभावित है।

15. इस विवरण में परिगणित राजकोषीय समेकन रूपरेखा को सचेत प्रयास से तैयार किया गया है ताकि सरकार के कुल व्यय को स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में संकट-पूर्व स्तर अर्थात् 2007-08 के स्तर तक लाया जा सके। राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी की गई सब्सिडियों के बदले प्रतिभूतियों के स्थान और निर्गत प्रतिभूतियों सहित जारी 2007-08 के दौरान, सरकार का कुल व्यय स.घ.उ. का 15.9 प्रतिशत था। यह 2008-09 में 17.3 प्रतिशत हो गया (सब्सिडियों के स्थान पर जारी प्रतिभूतियों सहित) तथा संशोधित अनुमान 2010-11 में कम होकर 15.4 प्रतिशत रह गया। विकासात्मक पक्ष पर व्यय के पुनः प्राथमिकता देने तथा गैर विकासात्मक व्यय में वृद्धि को कम करने के साथ, बजट अनुमान कम करके 2014-15 में कुल व्यय स.घ.उ. का 13.7 प्रतिशत तक अनुमानित है। मध्यावधि लक्ष्य की दृष्टि से यह कम होकर 2015-16 में स.घ.उ. का 13.4 प्रतिशत तथा 2016-17 में 12.8 प्रतिशत होना अनुमानित है।

राजकोषीय संकेतकों में अन्तर्निहित अवधारणाएं

1. राजस्व प्राप्ति

क कर राजस्व

16 स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में, उच्च आर्थिक विकास पर होते हुए तथा कर-सुधार उपायों की लाभकारी सूची द्वारा सहायता प्राप्त करके कर राजस्व 2007-08 में अपने शीर्ष पर था तथा 11.9 प्रतिशत के स्तर पर आ गया था। 2003-08 पांच वर्ष की अवधि के दौरान, औसत वार्षिक कर वृद्धि 21.3 प्रतिशत थी जबकि 2006-07 में वार्षिक कर वृद्धि अधिकतम 28.9 प्रतिशत के स्तर पर थी। ये सुधार मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर द्वारा किए गए हैं। जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि इस अवधि के दौरान लगभग 28 प्रतिशत थी। स.घ.उ.

के संदर्भ में कर राजस्व की उछाल इस अवधि के दौरान लगभग 1.5 रही।

17. उच्च कर वृद्धि का यह रुझान वैश्विक आर्थिक संकट के कारण मंदा हो गया और कर-स.घ.उ. का अनुपात 2008-09 में गिरकर 10.8 प्रतिशत हो गया और 2009-10 में गिरकर 9.7 प्रतिशत तक हो गया। 2010-11 में आर्थिक बहाली के प्रारंभिक संकेतों तथा प्रोत्साहन उपायों को आंशिक रूप से वापस लेने के साथ, कर-स.घ.उ. का अनुपात बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया जिसके साथ 27% की उच्च वृद्धि दर कर राजस्व में देखी गई क्योंकि प्रोत्साहन उपाय मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष कर के पक्ष में थे, आंशिक वापसी से 2009-10 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 2010-11 में अप्रत्यक्ष करों में 40.7% उच्च वृद्धि हुई तथापि, 2011-12 में 6.2 प्रतिशत पर आर्थिक वृद्धि में मंदी के साथ, पिछले वर्ष की तुलना में कर संग्रहणों ने 12.1 प्रतिशत दर्ज की। जिसके परिणामस्वरूप कर और स.घ.उ. का अनुपात 9.1 प्रतिशत हो गया।

18. आर्थिक वृद्धि दर, जो 2011-12 में कम होनी प्रारंभ हुई और 2012-13 में लगातार कम होती रही, ने 2013-14 में सुधार का संकेत दर्शाया है तथापि, सुधार का रास्ता वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक भाग में विनिमय दर की अस्थिरता द्वारा नाकाफी और सीमित था। आर्थिक विकास में मंदी के कारण, वास्तविक सकल कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट अनुमानों से तुलना ₹41378 करोड़ रुपए कम था। 2012-13 में कर-स.घ.उ. अनुपात 10.2 प्रतिशत जिससे 66.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 19.1 प्रतिशत बजटीय व्यवस्था की तुलना में प्रथम छमाही में घटकर सकल कर राजस्व 8 प्रतिशत हो गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में तदनुसूची अवधि की तुलना में सांकेतिक अर्थ में ₹5496 करोड़ के कम संग्रहण के चलते ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष के पूर्वार्द्ध में सीमा शुल्क मामूली रूप से 5.7 प्रतिशत बढ़ा है जिससे इस अवधि में अप्रत्यक्ष करों में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष कर संग्रहण अप्रत्यक्ष कर से बेहतर रहे, जिससे पूर्वार्द्ध में 11.5 प्रतिशत की गई, में कमी लाने की बजट में व्यवस्था की गई है।

19. समग्र रूप से कर संग्रहण बाह्य रुकावटों के कारण पहली छमाही में कम रहे और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में नकारात्मक रुख रहा। तथापि, वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में सकारात्मक नीती उपायों से स्थिति में बदलाव आया जिससे विदेशी अंतर्वाहों में तेजी आई, भुगतान स्थिति का सन्तुलन बेहतर हुआ और मुद्रास्फीति में नरमी आई। निर्यातों में तेजी आई तथा सकारात्मक अर्थव्यवस्था चयन से पुनरूद्धार की संभावना थी। उसी समय पर, सरकार ने राजकोषीय घाटे को लक्षित स्तरों के भीतर सीमित करने हेतु संसाधन जुटाने और व्यय नियंत्रण करने के लिए उपायों किये। कर संग्रहणों विशेष रूप से प्रत्यक्ष करों और सेवा कर में तेजी आई जबकि अप्रत्यक्ष पक्ष पर, संशोधित अनुमानों को घटाना

पड़ा। ब.अ. की तुलना में स.अ.2013-14 में प्रत्यक्ष करों में 4.8 प्रतिशत की कमी की गई जबकि अप्रत्यक्ष करों में 8.1 प्रतिशत की कमी की गई। इस प्रकार, कुल कर राजस्व प्रारंभिक अनुमानों को 6.2 प्रतिशत तक घटाकर संशोधित किया गया। परिणामतः बजट अनुमानों की तुलना में ₹ 76,964 करोड़ की कमी हुई। यह कमी ज्यादातर मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष करों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आई। 2013-14 के दौरान, पूर्वानुमानित कर वृद्धि 2012-13 के मुकाबले 11.8 प्रतिशत है और कर सघउ अनुपात 10.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2012-13 के स्तरों के मुकाबले आंशिक रूप से कम है।

20. वर्ष 2014-15 हेतु अनुमान वास्तविक अर्थव्यवस्था सुधार और 2013-14 के लिए बजट में घोषित किये गए कर उपायों के समुच्चय की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये गए हैं। यह आशा भी की जाती है कि सख्ती से कार्यान्वयन की और उन्मुखी प्रशासनिक मशीनरी में सुधारों से परिणाम मिलेंगे।

कर उपायों के ब्यौरे

21. इन उपायों से, ब.अ. 2013-14 में कर राजस्वों में 19.0 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य किया गया है। 2014-15 के लिए बजट में अनुमानित कर-सघउ अनुपात 10.7 प्रतिशत है। 2014-15 के लिए बजट अनुमान सं.अ. 2013-14 के मुकाबले 17 प्रतिशत की साधारण कर वृद्धि और शेष कर वृद्धि अतिरिक्त संसाधन जुटाने वाले उपायों से उत्पन्न होने की अवधारणा करता है।

22. कर सुधार और कर प्रयास राजकोषीय समेकन की समग्र प्रक्रिया हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक हैं। सन्तुलित और महत्वाकांक्षी कर वृद्धि के बिना सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय रोडमैप को प्राप्त करना सम्भव नहीं है। कर अनुमानों के वास्तविक होने की अपेक्षा की जाती है जबकि उसी समय अपेक्षित व्यय सम्पीड़न से अधिक का सहारा लिये बिना राजकोषीय रोडमैप को प्राप्त करने के लिए सरकार को समर्थ बनाने हेतु उनके महत्वाकांक्षी होने की आवश्यकता होती है। समग्र रूप से, कर को सघउ के प्रतिशत के रूप में बढ़ना चाहिए जबकि व्यय को जब तक राजकोषीय समेकन लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किये जाते, सघउ के प्रतिशत के रूप में प्रगामी रूप से कम होना चाहिए। अंतिम उद्देश्य संकट-पूर्व स्तरों के कर-सघउ अनुपात को वापस लाना होना चाहिए जबकि यह राजकोषीय समेकन की अवधि से धीरे-धीरे अंशशोधित होना चाहिए। चूंकि कर-सघउ अनुपात बढ़ता है, इसमें आगे सुधार अधिक धीरे होंगे और इन्हें प्राप्त करना कठिन होगा। 2015-16 और 2016-17 वर्षों के लिए कर राजस्वों हेतु दृष्टिकोण इसे ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जैसाकि उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है कर-सघउ अनुपात 2015-16 में 11.2 प्रतिशत और 2016-17 में 11.5 प्रतिशत पर पहुँचने का अनुमान है। इससे अभिप्राय 1.22 औसत उछाल से है जो वास्तविक तो है लेकिन एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसके लिए 16.4 प्रतिशत की औसत कर वृद्धि की अपेक्षा होगी जो बेहतर कर प्रयास और कतिपय एआरएम उपायों के संयोजन के जरिये संभव होगी।

(ख) राज्यों को अंतरण

23. केंद्रीय कर के शुद्ध आगमों में राज्यों का हिस्सा 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित है, जिसमें शुद्ध आगमों के 32 प्रतिशत को राज्यों को उनके हिस्से के रूप में देने की सिफारिश की गई है। अनुमान अवधि ने 13वें वित्त आयोग की समय सीमा को लांघ दिया है और यह नये गठित 14वें वित्त आयोग को प्रदत्त अवधि के प्रथम वर्ष तक पहुँच गई है। यह परिकल्पना की गई है कि राज्यों का हिस्सा इस परिवर्तन के बावजूद अनुमान अवधि से अधिक स्थिर बना रहेगा क्योंकि परिकल्पना के लिए कोई बेहतर आधार उपलब्ध नहीं है। इस दस्तावेज में तैयार की गई राजकोषीय योजना पुनः तैयार की जाएगी यदि 14वां वित्त आयोग राज्यों के हिस्से में परिवर्तन करता है।

(ग) कर-भिन्न राजस्व

24. केन्द्र का कर - भिन्न राजस्व मुख्य रूप से सरकार की ब्याज और लाभांश प्राप्तियों, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्तियों, जैसे विभिन्न अभिकरणों को केंद्रीय पुलिस बल की पूर्ति, पासपोर्ट और वीजा जारी करना, कंपनियों के पंजीकरण, पेटेंट्स और लाईसेंस शुल्क, अप-तटीय तेल क्षेत्रों से रॉयल्टी, पेट्रोल से लाभ और दूरभाष क्षेत्र से विभिन्न प्राप्तियां, से मिलकर बना है। चालू वर्ष के दौरान ₹ 40,000 करोड़ की ब्राडबैंड वायरलेस एक्सेस स्पैक्ट्रम की नीलामी और दूरभाष क्षेत्र की अन्य एक-मुश्त प्राप्तियों से बजटीय व्यवस्था की गई थी, जिन्हें वित्त वर्ष के अंत में सफल स्पैक्ट्रम नीलामियों का अनुकरण करके मूर्त रूप दिया जाना सम्भावित है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सीपीएसई द्वारा लाभांश अदायगियों और कोल इंडिया लि. द्वारा विशेष लाभांश अदायगी से उच्चतर प्राप्तियों के कारण बजट अनुमानों की तुलना में उच्चतर संग्रहण हैं। अन्य कर-भिन्न राजस्वों ने भी बजट अनुमानों की तुलना में सन्तुलित वृद्धि दर्शायी है। समग्र रूप से कर-भिन्न प्राप्तियां 2013-14 में सघउ का 1.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।

25. सरकार की ब्याज प्राप्तियां मुख्य रूप से रेलवे, राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दिये गए ऋणों से हैं। राज्यों से ब्याज प्राप्तियां समग्र रूप से कम हो रही हैं क्योंकि राज्यों से निवल ऋण 12 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार मध्यस्थता हटाने के पश्चात् उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। केन्द्र की लाभांश प्राप्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंक तथा दूसरा विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यम। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांशों में जैसे उनके लाभ में वृद्धि के साथ वृद्धि होनी चाहिए जबकि ये सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार के हिस्से के विनिवेश के कारण संतुलित होंगे। इसके विपरीत, चूंकि सरकार बेसल iii की सीआरएआर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंकों में इक्विटी का निवेश करेगी, बैंकों से लाभांश लाभ में वृद्धि और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार के हिस्से में वृद्धि के संयुक्त प्रयास के कारण तुलनात्मक रूप से तेजी से बढ़ेंगे। इन अवधारणाओं से 2014-15 में केन्द्र के कर-भिन्न राजस्व

सघउ के 1.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, इस तथ्य के कारण कि कर-भिन्न राजस्व विशेष लाभांश भुगतान के कारण वित्त वर्ष 2013-14 में सुदृढ़ किए गये थे, सं.अ. 2013-14 से नकारात्मक वृद्धि अनुमान है। विशेष लाभांश के बिना, ब.अ. 2014-15 में कर-भिन्न राजस्व सांकेतिक अर्थों में पिछले वर्ष के समतुल्य हैं।

26. उपर्युक्त अवधारणाओं का अधितकर अनुकरण करके, 2015-16 और 2016-17 हेतु कर-भिन्न राजस्वों के लिए दृष्टिकोण बना लिया गया है। 2014-15 में बजटीय कतिपय एक-मुश्त प्राप्तियां 2015-16 और 2016-17 में उपलब्ध नहीं होंगी। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांशों के सम्बंध में, सरकार की नीति उनकी पूंजी परियोजनाओं में उनकी सुरक्षित आयों का निवेश करने में उनको समर्थ बनाने के लिए होगी। तथापि, किसी ठोस पूंजी निवेश योजना के अभाव में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उनकी नकदी आधिक्य सरकार और अन्य शेयर धारकों को लाभांश के रूप में अदा करना चाहिए। दूरभाष क्षेत्र से यह अवधारणा की गई है कि पूर्व में 20 वर्षों हेतु जारी लाईसेंसों का नवीकरण अनुमान अवधि के दौरा नवीकरण हेतु आयेगा। फरवरी, 2014 में आयोजित स्पैक्ट्रम नीलामियों की सफलता आबंटन की अवधि से सतत् आधार पर उच्चतर राजस्वों में बदल जाएगी। यह सरकार हेतु आय स्थायी प्रवाह होगी। अवधारणाओं पर आधारित, 2015-16 और 2016-17 के लिए कर-भिन्न राजस्व क्रमशः स.घ.उ. का 1.3 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत होने के अनुमान लगाये गये हैं।

2. पूंजी प्राप्तियां

(क) ऋणों और अग्रिमों की वसूली

27. राज्यों से ऋणों की निवल वसूली में 12वें वित्त आयोग को प्रदत्त अवधि के दौरान कमी आई है जिसके कारण केंद्रीय सरकार द्वारा क्रमिक मध्यस्थता को हटाना और ऋण समेकन तथा ऋण माफी योजना हैं। चूंकि राज्य सरकारों को अब ऋण नहीं दिये जाते हैं, यह प्राप्ति वर्षानुवर्ष कम होगी क्योंकि पुराने ऋण परिसमाप्त हो जाते हैं। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से ऋणों का पुनर्भुगतान भी सरकारी क्षेत्र के उद्यम जो या तो रुग्ण हैं अथवा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के जरिए पुनरुद्धारधीन हैं से चूकों के कारण प्रभावित होगा। रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के ब्याज माफी अथवा ऋणों को बड़े खाते डालने से सम्भावित भावी प्राप्तियों में कमी आई है। ब.अ. 2013-14 में ₹10,654 करोड़ की ऋणों और अग्रिमों की वसूली का अनुमान लगाया गया था। तथापि, यह सं.अ. 2013-14 में ₹ 10,803 करोड़ तक संशोधित की गई थी। ब.अ. 2014-15 में इसका ₹ 10,527 करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। 2015-16 और 2016-17 के लिए, प्राप्ति का यह घटक सीधे ₹ 10,000 करोड़ रहने का अनुमान लगाया है क्योंकि सरकार निवल उधार को बढ़ावा नहीं देगी (राज्यों को बाह्य ऋणों हेतु की गई बेक-टू-बेक व्यवस्था हेतु स्वीकृति)।

(ख) अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्रतियां

28. इस शीर्ष के तहत प्राप्तियों का मुख्य स्रोत सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश है। पूर्व में, सरकार ने पृथक रूप से समेकित निधि (सीएफआई) के भीतर विनिवेश से आवकों

का हिसाब रखने के लिए और इसे आयोजना परिव्यय के भीतर आस्तियों के सृजन की तरह निर्धारित करने के अंतर्गत उपाय के रूप में राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) का सृजन किया था। तथापि, वित्त वर्ष 2013-14 से सरकार ने इस इरादे से कि विनिवेश से प्राप्तियां केवल विशिष्ट प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए निर्धारित की जाएंगी, सरकारी खाते के अंतर्गत पृथक निधि, एनआईएफ के सृजन का निर्णय लिया। इस बड़े उपाय से, प्राप्ति सरकार के सतत खर्चों के निधिपोषण हेतु उपलब्ध नहीं होंगी। ब.अ. 2013-14 के ₹55,814 करोड़ के मुकाबले सं.अ. 2013-14 में ₹20,841 करोड़ पर नियत किया गया है। इस कमी को प्रतिकूल बाजार स्थितियों के विरुद्ध देखा जाना चाहिए।

29. ब.अ. 2014-15 में, यह अनुमान लगाया गया है कि ₹51,925 करोड़ की धनराशि विनिवेश से एनआईएफ के तहत उपचित होगी। जिसमें निजी कंपनियों में सरकारी पण्य के विनिवेश से प्राप्तियां शामिल हैं जो वित्त वर्ष 2013-14 में मूर्त रूप ले सकती हैं। अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्रप्तियों में राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा ऋणों का पुनर्भुगतान शामिल है। यह धनराशि वर्षों से कमोवेश बराबर बनी हुई है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा स्थिरता के विरुद्ध लोचनीय बनाने के लिए प्रारक्षित निधियों के सृजन के इसके प्रयास के भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा रखे गए एसडीआर क्रय करने का प्रस्ताव किया है और यह प्रायोगिक आधार पर कुछ एसडीआर खरीदेगा। इस लेन-देन में प्राप्त राशि विविध पूंजी प्रप्तियों का भाग बनेगी। तदनुसार, कुल प्रप्तियां 2013-14 के ,सं.अ. और 2014-15 के ब.अ. में क्रमशः ₹36,644 करोड़ और ₹67,452 करोड़ रूपए बैठती हैं। मध्यावधि रूपरेखा में, वर्ष 2015-16 और 2016-17 हेतु प्रत्येक में ₹55,000 करोड़ की राशि ली गई है।

30. समग्र केन्द्रीय सरकार के ऋण का लगभग 92 प्रतिशत घरेलू ऋण और मात्र 8 प्रतिशत विदेशी ऋण है। 2013-14 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे के 89.2 प्रतिशत के वित्तपोषण हेतु, 2013-14 में ₹ 4,84,000 करोड़ की निवल बाजार उधारों की बजटीय व्यवस्था की गई थी। सकल राजकोषीय घाटे के शेष 13.5 प्रतिशत के वित्तपोषण हेतु वित्तपोषण के अन्य स्रोतों जैसे विदेशी सहायता, राज्य भविष्य निधियां और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से बजटीय व्यवस्था की गई थी। विदेशी उधार बजट में अनुमानित उधारों की अपेक्षा काफी कम रहे। तथापि, राज्य भविष्य निधियों से अपेक्षाकृत अधिक प्राप्ति हुई। गैर प्रतिरोधी नीलामी राजकोषीय हुंडियों में राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक निवेश के कारण राजकोषीय हुंडी वसूली भी बढ़ी। यह मुख्यतः राज्य सरकारों की संतोषजनक नकदी स्थिति तथा मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियों के मुकाबले राजकोषीय हुंडियों की नीलामी में उच्च ब्याज दरों के कारण रही। वर्ष के दौरान बेहतर राजकोषीय प्रबंध किए जाने से वित्त वर्ष 2013-14 के लिए ₹15000 करोड़ से ₹ 4,68,902 करोड़ तक बाजार उधारों में काफी कमी हुई। इसके अंतर्गत स्फीति आधारित बांडों से प्राप्त ₹ 6,500 करोड़ की राशि भी सम्मिलित है। वर्ष के दौरान उधार कार्यक्रम पूर्वघोषित उधार कलेण्डर के अनुरूप सुचारु रूप से पूरा किया गया। वर्ष 2013-14

के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों की भारत औसत परिपक्वता बढ़कर 14.34 वर्ष हो गई है जबकि पिछले वर्ष यह 13.50 वर्ष थी। इससे सरकार के बकाया ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए लगातार प्रयास परिलक्षित होते हैं। वर्ष के दौरान निर्गमों की भारत औसत प्राप्तियां मामूली रूप से बढ़कर 8.47 प्रतिशत हो गई जबकि पिछले वर्ष यह 8.36 प्रतिशत थी। प्राप्तियों में वृद्धि परिपक्वता अवधि बढ़ाने तथा प्राप्तियों की वृद्धि के चलते हुई।

31. सरकार की वित्तीय सुदृढीकरण उपाय जारी रखने की वचनबद्धता का अनुसरण करते हुए 2014-15 के लिए राजकोषीय घाटा कम करके सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत करने की बजटीय व्यवस्था की गई है। 2014-15 के लिए कुल उधार की जरूरत ₹ 5,96,083 करोड़ अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 प्रतिशत रखने की बजटीय व्यवस्था की गई है। राजकोषीय घाटे के लगभग 86.5 प्रतिशत का वित्तपोषण करने के लिए ₹4,57,322 करोड़ के निवल बाजार उधार की बजटीय व्यवस्था की गई है। वास्तविक अर्थों में निवल बाजार अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में 2.5 प्रतिशत की कमी दर्शाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के अर्थ में निवल बाजार उधार वित्त वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमान में 4.0 प्रतिशत की तुलना में गिरकर 3.6 प्रतिशत रखने की बजटीय व्यवस्था की गई है। विदेशी ऋण के जरिए उधारों के 2014-15 के दौरान तुलनात्मक रूप से महत्वहीन बने रहने की बजटीय व्यवस्था की गई है।

32. वाणिज्यिक बैंक प्रमुख निवेशक प्रवर्ग है। यह इस समय बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों का लगभग 48 प्रतिशत धारण करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि में वर्षानुवर्ष 15.7 प्रतिशत (24 जनवरी, 2014 की स्थिति के अनुसार) की वृद्धि दिखाई दी है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 13.1 प्रतिशत से अधिक है। बीमा कंपनियां सरकारी प्रतिभूतियों में अन्य प्रमुख निवेशक प्रवर्ग है। दीर्घकालिक प्रतिभूतियों से इसकी परंपरागत मांग रही है। सितंबर 2013 की समाप्ति पर केन्द्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों को धारण करने में बीमा कंपनियों का हिस्सा बढ़कर 19.3 प्रतिशत हो गया है जबकि पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति पर यह 18.6 प्रतिशत था। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए भविष्य निधियां दूसरा स्थायी स्रोत हैं। जिसका हिस्सा स्थायी रूप से लगभग 7.2 प्रतिशत बैठता है। इस प्रकार सरकार के निवल बाजार उधारों में बजट अनुमानित वृद्धि के मुकाबले वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं में काफी उच्चतर वृद्धि से यह अभिप्राय है कि 2014-15 के लिए सरकार के उधार कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से पूर्ण हो जाएंगे और यह निजी क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर बिना दबाव डाले होगा। इसके अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों के धारण में भविष्य निधियों के हिस्से में स्थिरता और बीमा कंपनियों के वर्धित हिस्से से लागत बढ़ाए बिना सरकारी ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल को और बढ़ाने की गुंजाइश होगी। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार की कुल देनदारियों में भी विगत हाल की प्रवृत्तियों के जारी रहने से गिरावट देखी जा सकती है। 2013-14 के अंत में सरकारी कुल देनदारी सकल घरेलू उत्पाद की 46.0 प्रतिशत अनुमानित है जो 2014-15 के अंत तक घटकर 44.8 प्रतिशत रह जाएगी। ह्रासकारी

प्रवृत्ति जारी रहने से इसके 2015-16 में घटकर 43.1 प्रतिशत और 2016-17 में 41.0 प्रतिशत रह जाने की संभावना है। ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में प्रगामी कमी सरकार के ब्याज भार को कम करेगी और सरकार को अतिरिक्त उधार का सहारा लिए बगैर विशेषकर अवसंरचना विकास पर व्यय करने की अधिक गुंजाइश देगी।

33. सकल घरेलू घाटा 2014-15 में प्रगामी रूप से गिरकर 4.2 प्रतिशत पर आने का अनुमान है। मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में सकल राजकोषीय घाटा और गिरकर 2015-16 तक 3.6 प्रतिशत और 2016-17 तक 3.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बाजार उधारों को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 86 प्रतिशत का वित्तपोषण मानते हुए निवल बाजार उधारों के अगले तीन वर्ष में महत्वपूर्ण रूप से गिरकर 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.6 प्रतिशत, 2015-16 में 3.1 प्रतिशत और 2016-17 में 2.6 प्रतिशत रहने की संभावना है। सरकारी ऋण के कम होने के चलते निजी निवेश और पूंजी अंतर्वाहों के लिए अतिरिक्त गुंजाइश रहेगी। यह स्फीतिकारी दबाव को भी कम करेगी और मौद्रिक नीति को सहज बनाने में भारतीय रिजर्व बैंक को सुखद स्थिति में रखेगी।

3. कुल व्यय

(1) राजस्व लेखा

(i) आयोजना राजस्व व्यय

34. सरकार का आयोजना राजस्व व्यय ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 4.2 प्रतिशत के औसत स्तर पर बना रहा है। तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक मंदी को रोकने के लिए किए गए प्रोत्साहन उपायों के कारण बारहवीं योजना अवधि के दौरान समग्र आयोजना व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत था।

35. सतत आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय समेकन के दोहरे लक्ष्य पूरे करने के लिए यह अति आवश्यक है कि आयोजना व्यय इष्टतम स्तरों पर रखा जाए। 2008-09 के दौरान सरकार तभी राजकोषीय विस्तार कर सकी क्योंकि यह न्यून राजकोषीय घाटे में चल रही थी और अपने घाटे में वृद्धि को वहन कर सकती थी। इस तरह की नीति का तब तक दोबारा अनुपालन नहीं किया जा सकता जब तक राजकोषीय घाटा कम करके स्वीकार्य सीमा में न लाया जाए। हालांकि, प्रयास सरकार का अनुत्पादक व्यय घटाने पर होना चाहिए और कम से कम राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया पूरी होने तक आयोजना व्यय संभाले जा सकने वाले स्तरों पर बनाए रखना होगा।

36. वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजना व्यय युक्तिसंगत बनाकर सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत और 2014-15 के बजट अनुमान में आयोजना व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 4.2 प्रतिशत पर होगा। 2014-15 का आयोजना व्यय 2013-14 के बजट अनुमान के स्तर पर ही रखा गया है जो 2013-14 के संशोधित अनुमान का 16.8 प्रतिशत बैठता है। संशोधित एफआरबीएम नियमों में अपनाए गए राजकोषीय समेकन के रोडमैप के अनुसार राजकोषीय लक्ष्यों और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आकलनों के दौरान आयोजना व्यय का अनुमान लगाया गया है। तदनुसार, यह अनुमानित है कि आयोजना व्यय के लिए संसाधन वित्त वर्ष

2015-16 और 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 4.3 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत होंगे।

(ii) आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

सरकार के आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय में मुख्यतया इसके स्थापना व्यय, ब्याज अदायगियां, रक्षा व्यय, सब्सिडियां, राज्यों को सांविधिक अनुदान और अन्य अवशिष्ट मदें सन्निहित हैं। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय मुख्यतया छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 8.4 प्रतिशत से उछल कर 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद का 10.2 प्रतिशत हो गया। तब से सरकार द्वारा किए गए विभिन्न व्यय सुधार उपायों के कारण 2014-15 के बजट अनुमान में यह कम होकर 8.6 प्रतिशत रह गए हैं। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय 2013-14 के संशोधित अनुमान में ₹ 10.28 लाख करोड़ और 2014-15 के बजट अनुमान में ₹ 11.08 लाख करोड़ होना अनुमानित है। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के विभिन्न संघटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(क) ब्याज अदायगियां

38. सरकार द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय विस्तार के कारण वैश्विक आर्थिक संकट के बाद ब्याज अदायगियां तेजी से बढ़ी हैं। केन्द्र के निवल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियां 2007-08 में 38.9 प्रतिशत से उछल कर 2008-09 में 43.4 प्रतिशत और फिर 2009-10 में 46.7 प्रतिशत हो गई। चालू वर्ष में ब्याज अदायगी के निवल कर के 45.5 प्रतिशत पर होगी। हाल की अवधि के दौरान जिन कारकों ने ब्याज अदायगी प्रभावित की है वे 2011-12 के दौरान वित्तीय विसर्पण के साथ प्रोत्साहन उपायों के कारण वृद्धित ऋण स्टॉक और तुलनात्मक रूप से आजकल विद्यमान कठोर ब्याज दर व्यवस्था हैं।

39. वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में राजकोषीय समेकन के अनुकरण में गिरावट दर्शाते ब्याज अदायगी केन्द्र को निवल कर का 43.3 प्रतिशत अनुमानित है। सरकारी घाटे के कम होने और मुद्रा स्फीति नियंत्रित करने के सरकार के प्रयासों के चलते यह संभावना है कि आगामी वर्षों में ब्याज दरें गिरेंगीं। घाटे में कमी और ब्याज दरों में गिरावट निजी क्षेत्र को निम्न लागत पर संसाधन जुटाने की सकारात्मक गुंजाइश सृजित करेगी।

(ख) रक्षा सेवाएं

40. राजस्व लेखे पर रक्षा व्यय मुख्यतया रक्षा बलों के वेतन व्यय और उनके प्रचालनात्मक व्यय से बनता है। रक्षा राजस्व व्यय 2013-14 के बजट अनुमान में ₹ 1.24 लाख करोड़ और 2014-15 के बजट अनुमान में ₹ 1.34 लाख करोड़ अनुमानित है। अनुमान की अवधि के दौरान रक्षा राजस्व व्यय 7.7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

(ग) पेंशन

41. केन्द्र सरकार की पेंशन अदायगियों संबंधी व्यय में रक्षा के साथ-साथ सिविल पेंशन शामिल है। सांकेतिक अर्थ में पेंशन अदायगी 2013-14 के संशोधित अनुमान में ₹ 74,076 करोड़ और

2014-15 के बजट अनुमान में ₹ 80,983 करोड़ अनुमानित है। पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र सरकार का पेंशन भुगतान वेतन व्यय की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण अधिक सेवानिवृत्तियों और वृद्धित जीवन प्रत्याशा के कारण पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होना है। तदनुसार, विगत प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार का पेंशन व्यय 9.3 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

(घ) राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान

42. राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान मुख्यतया वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों से बनते हैं। वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमान में आयोजना-भिन्न अनुदान 55,290 करोड़ और 2014-15 के बजट अनुमान में 64,675 करोड़ अनुमानित हैं। 2014-15 के बजट अनुमान में राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर की हानि की प्रतिपूर्ति भी शामिल है जो वस्तु और सेवा कर को अंतिम रूप दिए जाने की ओर केन्द्र और राज्यों के बीच करार के लिए महत्वपूर्ण है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी क्षतिपूर्ति 2015-16 में भी जारी रहेगी, 2015-16 का अनुमान लगाया गया है।

43. 2015-16 में योजना-भिन्न अनुदानों 2014-15 की तुलना में थोड़ी सी बढ़ाई गई है क्योंकि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें प्रभावी हो जाएगी। सामान्यतः वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों प्रदान की गई अवधि के दूसरे वर्ष से प्रवाह करने हेतु संस्तुत हैं ताकि राज्य सरकारों के लिए आसान तैयारी अवधि सुनिश्चित की जा सके। इन धारणाओं पर योजना भिन्न अनुदानों 2015-16 तथा 2016-17 में स.घ.उ. को 0.5 प्रतिशत पर अनुमानित की गई है।

(ङ) मुख्य सब्सिडियां

44. 2013-14 के लिए संशोधित अनुमानों में मुख्य सब्सिडियां ₹ 2,20,972 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में ₹ 2,45,452 करोड़ तक बढ़ा दी गयी है। वृद्धि का मुख्य अंश पेट्रोलियम सब्सिडियों से आया है जो बजट अनुमान 2013-14 में ₹ 65,000 करोड़ से संशोधित अनुमान 2013-14 में ₹ 85,480 करोड़ हो गया है। बजट अनुमान 2014-15 में मुख्य सब्सिडियों के लिए 2,46,397 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई है। संशोधित अनुमान 2013-14 में कुल सब्सिडियाँ स.घ.उ. का 2.2 प्रतिशत है तथा 2014-15 में स.घ.उ. के 1.9 प्रतिशत की बजटीय व्यवस्था की गई है। आगे देखते हुए, आशा है कि मुख्य सब्सिडियों पर व्यय में नीतिगत सुधार और बेहतर लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 में कम होकर स.घ.उ. का क्रमशः 1.8 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत हो जाएगा।

45. मुख्य सब्सिडियाँ राजकोषीय समेकन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं तथा अपने राजकोषीय लक्ष्यों को पूरा करने में सरकार की सफलता को निर्धारित करने में सबसे मुख्य कारक हैं। सरकार का प्रयास इस मुद्दे को दो तरफा कार्यनिर्देश से निपटाने का होगा। पहले, सरकार को सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारण नीति से जुड़ना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल सब्सिडियाँ वहनीय स्तरों के अंतर्गत होती हैं। दूसरी बार, यह सुनिश्चित करना अत्यधिक आवश्यक है कि सरकार द्वारा प्रदान

की गई सब्सिडियों को बेहतर रूप से लक्ष्यगत करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां कार्यरत हैं।

46. सब्सिडियों को लक्ष्य बनाने में सुधार करने के लिए सरकार ने यूआईडी प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए लाभार्थियों के आधार से संबद्ध बैंक खातों में सरकारी लाभों की प्रत्यक्ष रूप से अंतरण के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यद्यपि, फिलहाल यह योजना सीमित जिलों में सीमित योजनाओं को कवर करते हुए प्रायोगिक अवस्था में है, जब यह प्रायोजिक योजना संतोषजनक पायी जाएगी, तो प्रणाली को लाभों के विभिन्न अंतरणों हेतु देश भर में फैलाया जा सकता है। चूंकि प्रणाली यूआईडी प्लेटफार्म पर आधारित है, प्रारंभ में यह सुनिश्चित करेगी कि नकली लाभार्थियों तथा अविद्यमान विद्यार्थियों को किए जाने वाले अंतरणों को शुरु से ही समाप्त किया जाएगा। यहां तक कि पात्रता के मुद्दे को भी बाद में आसानी से निपटाया जा सकता है।

47. मूल्यनिर्धारण मुद्दे पर, विशेष कर पेट्रोलियम के लिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु डीजल है जो राजकोषीय समेकन प्रक्रिया को सबसे ज्यादा जोखिम देती है। डीजल मूल्यनिर्धारण में सरकार के सामने आ रही मूलभूत समस्या यह है कि मूल्य ठीक करने में किसी भी विलंब से आगे मूल्य ठीक करने की शीघ्र जरूरत होती है और यह बहुत कठिन है। इससे नियंत्रित मूल्यों में उच्च सब्सिडी तथा दृढ़ता के दुष्प्रकार में तेजी आ जाती है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रति लीटर ₹ 5 की पर्याप्त मूल्य वृद्धि लागू करने के बाद, सरकार ने शीघ्रता के आधार पर 'लघु' मूल्य सुधार लागू करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को अनुमति प्रदान की है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता अपने उपर्युक्त संसाधनों से ठगा महसूस नहीं करेगा क्योंकि संशोधन बहुत कम होंगे और साथ ही साथ उनसे सरकार को अंतगोत्वा सरकार को नियंत्रण हटाने में मदद मिलेगी। इसे यह भी सुनिश्चित होगा कि स्फीति के संबंध में डीजल मूल्य वृद्धि का प्रभाव न्यूनतम हो यदि तेल सेक्टर में कोई अंतरराष्ट्रीय संकट नहीं आते हैं तो यह उम्मीद है कि एक-दो वर्षों में सरकार डीजल को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त करने में सक्षम होगी।

48. उर्वरकों के संबंध में, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था फॉस्फेटी पोटाशी क्षेत्रों में बढ़िया काम कर रही है। अभी जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है वे हैं यूरिया कतिपय मूल्य सुधार जिसमें यूरिया के तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है। यह न केवल सब्सिडी आकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाशी पोषक तत्वों ने संतुलित प्रयोग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आगे चलकर सरकार उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि के संदर्भ में काम करेगी। इसे आयात पर निर्भरता कम करने में तथा मूल्यों को अपेक्षाकृत अधिक स्थायी रखने में मदद मिलेगी।

49. आने वाले वर्षों में खाद्य सब्सिडी व्यवस्था में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने से अमूलचूर्ण परिवर्तन होगा। इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से सरकार का ध्यान सार्वजनिक वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने, वितरण श्रृंखला को बेहतर बनाने, भारतीय खाद्य निगम और अन्य सम्मिलित संगठनों की प्रयास लागत में कमी करने तथा अन्य संबंधित सुधार करने पर होगा।

50. जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है कि सब्सिडी सुधारों पर ध्यान दिए बगैर, राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया प्रायः असंभव हो जाएगी। प्रमुख सब्सिडियों पर सरकार का व्यय 2013-14 के संशोधित अनुमानों में दर्शित सकल घरेलू उत्पाद के 2.2 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 सकल घरेलू उत्पाद का 1.9 प्रतिशत होने की संभावना है। आशा है कि सकारात्मक नीतिगत सुधार किए जाने से यह घटना क्रमिक रूप से कम हो जाएगी। इस लक्ष्य अवधि के दौरान, यह प्रस्तावित है कि इसे 2015-16 और 2016-17 में क्रमशः 1.8 प्रतिशत एवं 1.6 प्रतिशत पर नियंत्रित किया जाए।

(ii) पूंजी परिव्यय

51. सरकार को कुल पूंजी व्यय का अनुमान वर्ष 2013-14 के दौरान के संशोधित अनुमानों में ₹ 1,90,894 करोड़ लगाया गया है और 2014-15 ने बजट अनुमानों में इससे बढ़कर ₹ 2,31,160 करोड़ तक अनुमान लगाया गया है। इसमें से, आयोजना व्यय संशोधित अनुमानों में ₹ 1,03,681 करोड़ होने की प्रत्याशा है जो और बजट अनुमानों में इसके बढ़कर ₹ 1,13,049 करोड़ तक होने की संभावना है। आयोजना भिन्न-पूंजी व्यय का संशोधित अनुमानों में ₹ 87,214 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है और 2014-15 में ₹ 1,00,111 करोड़ का होने की उम्मीद है।

52. आयोजना भिन्न-व्यय के संबंध में, पूंजी व्यय को प्रमुख अंश में रक्षा पूंजी व्यय में शामिल है। रक्षा पूंजी व्यय 2013-14 के संशोधित अनुमानों में ₹ 78,872 करोड़ होने की उम्मीद है और इसके बढ़कर 2014-15 बजट अनुमान ₹ 89,588 करोड़ होने की प्रत्याशा है। इस लक्ष्य अवधि के दौरान, पूंजी व्यय में 10 प्रतिशत होने की व्यवस्था है जो केन्द्र के संसाधनों के मांगों और समग्र साधन उपलब्धता के अनुरूप है।

53. भारत सरकार का आयोजना परिव्यय में मुख्यतः सकल रेलवे व्यय के लिए सकल बजटीय सहायता सरकारी कम्पनियों और बैंकों में राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश तथा राज्य सरकारों एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों को दिए जाने वाले ऋण सम्मिलित होते हैं। चूंकि समग्र प्रयास सरकार का राजस्व घाटा कम करना है, अतः आवश्यक है कि कुल आयोजना व्यय के भीतर, पूंजी संघटक सम्बन्धी व्यय राजस्व संघटक के मुकाबले अधिक बढ़े। आयोजना पूंजी व्यय 2014-15 में कुल आयोजना व्यय के 20 प्रतिशत की बजट व्यवस्था की जा रही है तथा इसके 2015-16 एवं 2016-17 में कुल आयोजना व्यय के 25 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है।

ग. 2014-15 से 2016-17 के दौरान राजकोषीय संभावना

54. 2013-14 का बजट घटती विकास दर ऊपर की ओर ले जाने की अर्थव्यवस्था के साथ सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत के अनुमानित राजकोषीय घाटे के साथ प्रस्तुत किया गया था। विकास दर दशक में पहली बार वित्त वर्ष 2012-13 में 5 प्रतिशत से नीचे दर्ज की गई। इसके 6 प्रतिशत से अधिक स्तरों पर वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि विकास प्रवृत्तियां उम्मीदों पर आधारित होती हैं। पिछले वर्ष से अधिक की विकास दर दर्ज करने के लिए घटती प्रवृत्ति को रोका जाना था। अमरीका में मात्रात्मक नरमी की सन्निकट आशंका से मुद्रा दर में अस्थिरता

तथा अन्य मुख्य अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर में कमी आने से व्यापार प्रभावित हुआ है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013 में कर संग्रहणों में मंदी छापी रही जो राजकोषीय घाटे के अतिक्रमण का खतरा बन गया।

55. तथापि सकारात्मक नीतिगत रूख निवेश बढ़ाने की दिशा में किए गए अनेक उपायों, स्वर्ण आयात कम करने के लिए की गई कार्रवाई और कारगर मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत हस्तक्षेपों से वृहद आर्थिक परिवेश में सुधार हुआ है। सुनिश्चित और यथासमय की गई कार्रवाई से दो तरफा घाटे को कम करने और विभिन्न वृहद आर्थिक मापदण्डों को सुधारने में मदद मिली है। दिसम्बर 2013 में, उच्चतम विदेशी निवेश अन्तर्वाह दर्ज किए गए, विदेशी मुद्रा भण्डार सुखद रहा और विनिमय दर काफी स्थिर रही। जब मात्रात्मक नरमी की वास्तविक क्रिया वर्ष के सम्बन्ध में शुरू हुई, उसका मामूली प्रभाव हुआ। मार्केट की उम्मीदों से परे व्यापार घाटा अपेक्षाकृत कम रहा। इसी प्रकार व्यय औचित्यकरण और संसाधन उगाही के सम्बन्ध में राजकोषीय दृष्टिकोण से किए गए समन्वित प्रयासों से राजकोषीय घाटे के प्रभाव को कम करने में मदद मिली। इस क्रम में राजकोषीय निवेश के स्पष्ट संकेत दिखाई दिए। परिणामस्वरूप, भारत में स्थित अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा काफी सुखद रही।

56. 2013-14 का बजट सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के अनुमान के साथ प्रस्तुत किया गया था। उस समय आर्थिक विकास में नरमी के संकेत पहले से ही दृष्टिगोचर हो गए थे। बजट अनुमानों से तुलना करने पर, 2012-13 के दौरान कर प्राप्तियां लगभग ₹41,378 करोड़ कम रही। तथापि वित्तीय समेकन से राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2012-13 की संशोधित अनुमानों से कहीं कम रहा। विवेक सम्मत राजकोषीय प्रबंध किए जाने से सरकार ने वर्ष की दूसरी छमाही में बढ़ते हुए घाटे को काफी हद तक नियंत्रित किया है। इसी प्रकार के उपाय 2013-14 में किए गए। परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बजट अनुमानों में लगाए गए 4.8 प्रतिशत के मुकाबले संशोधित करते हुए 4.6 प्रतिशत कर दिया गया।

57. वर्ष 2014-15 के लिए राजकोषीय नीति, सरकार द्वारा पहले घोषित की गई रूपरेखा की तर्ज पर बनाई गई है। तथापि, इस रोडमैप में लक्ष्य सुधारने के लिए सरकार ने अपना संकल्प दर्शाया है। वित्त वर्ष 2014-15 के रोडमैप में दिए गए 4.2 प्रतिशत की तुलना में प्रस्ताव है कि कर राजस्व और व्यय प्रबंधन के बेहतर संयोजन द्वारा 4.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। सरकार ने बजट में घोषित अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया की विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता दर्शाई है। उपर्युक्त सारणी में यथावर्णित सरकार के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य उसके द्वारा घोषित राजकोषीय समेकन की रूपरेखा के अनुरूप है। इस रूपरेखा में यह सुनिश्चित करने का उल्लेख किया गया है कि यह प्राप्य बना रहे और उसी समय के राजकोषीय समेकन की रूपरेखा के सम्बन्ध में सरकार की विश्वनीयता सुस्थापित हो। विविध संघटकों की धारणाएं इस अध्याय में वर्णित उपर्युक्त दी गई रूपरेखा के निर्माण खंड हैं।